रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266511
CG-DL-E-29092025-266511

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947
No. 634] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 718(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 129 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (य) के अनुसरण में और विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024, तारीख 10 अक्टूबर, 2024 को और भारत के राजपत्र में तारीख 14 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत वितरण (लेखे और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2025 है।

   (2) ये तारीख 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम विनिर्दिष्ट इकाई पर लागू होंगे।

3. **परिभाषा-(1)** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) **"अधिनियम"** से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

   (ख) "**अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण"** से इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए विवरणों को प्रकट करने वाले ब्यौरे अभिप्रेत हैं;

   (ग) **"कंपनी अधिनियम**" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(घ) "**वित्तीय विवरण**" से कंपनी अधिनियम की धारा 129 के साथ पठित धारा 2 के खंड (40) में निर्दिष्ट वित्तीय ब्यौरे अभिप्रेत है;

(ङ) "**वित्तीय वर्ष**" से कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (41) में निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(च) "**अनुसूची**" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) **"विनिर्दिष्ट इकाई"** से अधिनियम के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है, जिसमें सैन्य इंजीनियरिंग सेवाएं, नगर निगम या परिषद, बंदरगाह या ट्रस्ट, परिवहन उपक्रम, दामोदर घाटी निगम, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन शामिल नहीं किए गए सरकारी विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत के वितरण में पूरी तरह से लगी इकाई या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में छूट प्राप्त कोई अन्य इकाई शामिल नहीं है;

(ज) **"टैरिफ सब्सिडी "**से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अधीन परिभाषित उपभोक्ताओं की कतिपय श्रेणियों को सब्सिडी दरों पर विद्युत विक्रय के लिए किसी विनिर्दिष्ट इकाई को प्रदान की गई सब्सिडी अभिप्रेत है।

(झ) **"व्यापार प्राप्य"**से सामान्य व्यवसाय के दौरान दी गई विद्युत या संबंधित सेवाओं के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, उस अधिनियम या कंपनी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, में क्रमशः ऐसे शब्दों और पदों को दिए गए हैं।

4. **विनियामक आस्थगित खाता शेष या भावी टैरिफ से वसूली योग्य आय की मान्यता।**–(1) टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य दावों या राशियों के लिए, यदि कोई हो, तो विनिर्दिष्ट इकाई लागू लेखांकन मानकों और दर विनियमित क्रियाकलापों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन के अनुसार अपने वित्तीय टिप्पण विवरण में नियामक आस्थगित खाता शेष या भविष्य के टैरिफ से वसूली योग्य आय को मान्यता देगी।

(2) विनिर्दिष्ट इकाई वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए कम से कम वित्तीय वर्ष के अंत में वसूल, वापसी या समायोजित की जाने वाली अनुमानित राशि की समीक्षा करेगी।

(3) यदि अपेक्षा पिछले अनुमानों से भिन्न है, तो परिवर्तनों को लागू लेखांकन मानकों की सुसंगत अपेक्षाओं के अनुसार लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में हिसाब में लिया जाना चाहिए।

(4) विनिर्दिष्ट इकाई वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त ऐसे दावे या राशि की हानि के लिए, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से वसूली हेतु अनुमोदन उपलब्ध नहीं है, कम से कम, नीचे सारणी में उल्लिखित मानदंडों का पालन करेगी:-

सारणी

आयु: मान्यता के वर्ष से देय	प्रतिशत उपबंध
(1)	(2)
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष या उससे कम	25%
5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष या उससे कम	50%
7 वर्ष से अधिक	100%;

परंतु जहां विनिर्दिष्ट इकाई ने ऐसे वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त दावों या राशियों का दावा करने के लिए, तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार, समय सीमा के भीतर उपभोक्ताओं को पास-थ्रू के लिए उपयुक्त फोरम में याचिका या अपील दायर नहीं की है, विनिर्दिष्ट इकाई, ऐसी समय सीमा की समाप्ति के वर्ष में 100 प्रतिशत पर ऐसी शेष राशि का उपबंध करेगी।

दी गई सारणी के अनुसार होगी स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

(क) उपरोक्त उपबंध मानदंड तारीख 1 अप्रैल, 2026 के बाद उत्पन्न होने वाले शेष के लिए लागू होंगे;

(ख) तारीख 31 मार्च, 2026 तक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित शेष के लिए, निर्दिष्ट संस्था तारीख 31 मार्च, 2026 को ऐसे शेषों की मान्यता का वर्ष मानते हुए उपरोक्त उपबंध मानदंडों को लागू करेगी; और

(ग) फोरम से उपयुक्त आयोग या अपील न्यायालय अभिप्रेत है।

(5) विनिर्दिष्ट इकाई उस आधार का प्रकटीकरण करेगी जिस पर ऐसे दावों या राशियों को प्रारंभ में और बाद में मापा जाता है, जिसमें यह भी शामिल है कि ऐसी राशियों का वसूली के लिए मूल्यांकन कैसे किया जाता है और क्षति हानि का आवंटन कैसे किया जाता है।

(6) टैरिफ सब्सिडी को अधिनियम के अधीन बनाए गए सुसंगत नियमों के अनुसार मान्यता दी जाएगी और उसका लेखा-जोखा रखा जाएगा।

5. **व्यापार प्राप्तियों का उपबंध**वित्तीय विवरणों में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से अप -नी व्यापार प्राप्तियों पर एक विनिर्दिष्ट इकाई के लिए न्यूनतम उपबंध अपेक्षा नीचे:

सारणी

क्रम सं.	**भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियाँ**	**उपबंध का %**		
		वित्तीय वर्ष 2026-27	**वित्तीय वर्ष 2027-28**	**वित्तीय वर्ष 2028-29 और उसके बाद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0 से 90 दिन तक	-	-	-
2.	90 दिन से अधिक और 180 दिन तक	5%	10%	15%
3.	180 दिन से अधिक और 1 वर्ष तक	20%	25%	30%
4.	1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	35%	40%	45%
5.	2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	55%	60%	75%
6.	3 वर्ष से अधिक	75%	80%	100%
7.	स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट उपभोक्ताओं से बकाया	75%	75%	75%:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-:

(i) सरकारी उपभोक्ताओं से व्यापार प्राप्तियाँ; अथवा

(ii) विनिर्दिष्ट इकाई जिसके व्यापार प्राप्य दिन समग्र आधार पर नब्बे दिन से कम या उसके बराबर हैं:

परंतु यह और कि, अधिकारपूर्ण उपयुक्त आयोग राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर उच्चतर उपबंध अपेक्षा निर्धारित कर सकता है, जिसमें प्रमुख सचिव (विद्युत), प्रमुख सचिव (वित्त) और निर्दिष्ट इकाई के अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए पद -

(i) सरकारी उपभोक्ताओं से राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या उससे संबंधित विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और इसी तरह के अन्य अभिप्रेत है; और

(ii) व्यापार प्राप्य दिन से वित्तीय वर्ष के अंत में प्रति दिन औसत राजस्व से विभाजित व्यापार प्राप्तियाँ अभिप्रेत है ।

6. **अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरणों की विषय-वस्तु और स्वरूप- (1)** कंपनी अधिनियम के अधीन अधिदेशित वैधानिक प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, निर्दिष्ट इकाई अनुसूची में दिए गए प्रारूप और रीति से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण भी तैयार करेगी।

स्पष्टीकरण.-इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विनिर्दिष्ट इकाई के विद्युत संबंधी व्यवसाय के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण तैयार किए जाने अपेक्षित हैं।

(2) अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण विनिर्दिष्ट इकाई द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का हिस्सा होंगे और वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों के अंतर्गत 'अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण' शीर्षक वाले अंतिम प्रकटीकरण के रूप में वित्तीय विवरणों के साथ उपाबद्ध किए जाएंगे:

परंतु अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण तैयार करने के पहले वर्ष में, विनिर्दिष्ट इकाई के पास वार्षिक विवरणी या वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण शामिल करने का विकल्प होगा।

(3) अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरणों में जैसा कि नियम में उपाबद्ध निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात-

(i) वित्तीय विवरणों के पूरक प्रकटीकरण;

(ii) आपूर्ति की औसत लागत-औसत राजस्व प्राप्ति अंतर का विवरण; और

(iii) समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि का विवरण।

स्पष्टीकरण.- संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण तैयार करने के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े वैकल्पिक होंगे।

7. **अनुपालन का विवरण** -विनिर्दिष्ट इकाई का प्रबंधन अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण की शुरुआत में अनुपालन का विवरण देगा, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण अनुसूची में दिए गए प्ररूप और रीति के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं।

अनुसूची: अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण (एडीएस)

अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण 1: वित्तीय विवरणों के लिए पूरक प्रकटीकरण

1. **परिचालन से राजस्व:**

विवरण	**31 मार्च, 20... को समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष)**	**31 मार्च, 20... को समाप्त वर्ष के लिए (पिछले वर्ष)**
(1)	**(2)**	**(3)**
(क) ऊर्जा के विक्रय से राजस्व		
स्वयं के उपभोक्ताओं को विद्युत का विक्रय (लो टेंशन (एलटी), हाई टेंशन (एचटी) और एक्स्ट्रा हाई टेंशन (ईएचटी))		
ईंधन समायोजन शुल्क (एफएसी)/ईंधन लागत समायोजन (एफसीए)/ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए)/विद्युत क्रय समायोजन शुल्क (पीपीएसी)		
वितरण फ्रेंचाइजी को विक्रय		
अन्य को विद्युत का विक्रय (जैसे अंतर-राज्यीय विक्रय/ऊर्जा व्यापार/अनिर्धारित अंतर-परिवर्तन (यूआई)/विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम)/अंतर डिस्कॉम विक्रय, आदि)		

उपभोक्ताओं से अन्य प्राप्तियां (जैसे मीटर किराया, सेवा किराया, विद्युत चोरी और कदाचार के लिए वसूली, आदि)		
(i) कुल		
घटाएँ: उपभोक्ताओं को छूट (यदि कोई हो, नकद छूट के अलावा) (ii)		
टैरिफ सब्सिडी के बिना ऊर्जा के विक्रय से राजस्व (i-ii)		
उपभोक्ताओं को बिल किए गए विद्युत शुल्क/अन्य कर विद्युत शुल्क/अन्य देय कर सरकार को		
ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व का उप-योग		
(ख) अन्य परिचालन आय		
व्हीलिंग शुल्क		
खुली पहुंच शुल्क		
अन्य		
(ग) सब्सिडी		
राज्य सरकार द्वारा देय सब्सिडी, ऊर्जा लेखों के अनुसार सब्सिडी प्राप्त श्रेणियों को आपूर्ति की गई इकाइयों की संख्या के अनुसार प्रति यूनिट सब्सिडी से गुणा की जाती है		
प्राप्त सब्सिडी		
प्राप्त की जाने वाली सब्सिडी		
प्रचालन से कुल राजस्व (क+ख+ग)		

2. ऊर्जा की विक्रय से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा:

विवरण	**31 मार्च, 20.. को समाप्त वर्ष के लिए (चालू और पिछले वर्ष के लिए)**					
	विक्रय ऊर्जा – मीटरीकृत (एमयू)	**विक्रय ऊर्जा – गैर-मीटरीकृत (एमयू)**	**सकल ऊर्जा विक्रय (एमयू)**	**टैरिफ सब्सिडी के बिना ऊर्जा का विक्रय से राजस्व**	**बिल की गई टैरिफ सब्सिडी**	**प्राप्त टैरिफ सब्सिडी**
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)
घरेलू						
वाणिज्यिक						
कृषि						
औद्योगिक						
अन्य:						
सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग						
सार्वजनिक जल कार्य						
रेलवे						
थोक आपूर्ति						
वितरण फ्रेंचाइजी						
अंतर-राज्यीय विक्रय/ऊर्जा व्यापार/यूआई/डीएसएम						
अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट कर						

सकते हैं)						
(i) कुल						
उपरोक्त (i) में से सरकारी उपभोक्ताओं से संबंधित						
राज्य सरकार के उपभोक्ता						
केन्द्रीय सरकार के उपभोक्ता						

3. उपभोक्ताओं की संख्या का ब्यौरा:

विवरण	**31 मार्च, 20.. को समाप्त वर्ष के लिए (चालू और पिछले वर्ष के लिए)**											
	1 अप्रैल, 20.. तक की स्थिति के अनुसार				**वर्ष के दौरान**				**31 मार्च, 20.. तक की स्थिति के अनुसार**			
	प्रीपेड मीटर-उपभोक्ताओं की संख्या	**अन्य मीटर-उपभोक्ताओं की संख्या**	**गैर-मीटरीकृत - उपभोक्ताओं की संख्या**	**उपभोक्ताओं की कुल संख्या**	**जोड़े प्रीपेड मीटर - उपभोक्ताओं की संख्या**	**अन्य मीटर - जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या**	**गैर-मीटररकृत - उपभोक्ताओं की संख्या**	**स्थायी रूप से कनेक्शन से वंचित उपभोक्ताओं की संख्या**	**प्रीपेड मीटर-उपभोक्ताओं की संख्या**	**अन्य मीटर-उपभोक्ताओं की संख्या**	**गैर-मीटरीकृत - उपभोक्ताओं की संख्या**	**उपभोक्ताओं की कुल संख्या**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
घरेलू												
वाणिज्यिक												
कृषि												
औद्योगिक												
अन्य:												
सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग												
सार्वजनिक जल कार्य												
रेलवे												
थोक आपूर्ति												
विविध												
कुल												

4. **क्रॉस सब्सिडी का ब्यौरा:**

		31 मार्च, 20.. को समाप्त वर्ष के लिए (चालू और पिछले वर्ष के लिए)					
विवरण	**आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) (रु./किलोवाट घंटा)**	**अधिसूचित टैरिफ**	**अधिसूचित सब्सिडी**	**सकल ऊर्जा विक्रय (एमयू)**	**टैरिफ सब्सिडी के बिना ऊर्जा की विक्रय से राजस्व (करोड़ रुपये में)**	**औसत बिलिंग दर (एबीआर) (रु./किलोवाट घंटा)**	**क्रॉस सब्सिडी (रु./किलोवाट घंटा) (एसीओएस-एबीआर)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(2)-(7)
घरेलू							
वाणिज्यिक							
कृषि							
औद्योगिक							
अन्य:							
सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग							
सार्वजनिक जल कार्य							
रेलवे							
थोक आपूर्ति							
विविध							
कुल							

टिप्पण: (i) स्तंभ (2) में आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) का अर्थ लाभ और हानि विवरण के अनुसार कुल व्यय को विक्रय सकल ऊर्जा से विभाजित करना है;

(ii) स्तंभ (3) में अधिसूचित टैरिफ का अर्थ प्रासंगिक टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी पर लागू टैरिफ है;

(iii) स्तंभ (5) में सकल विक्रय ऊर्जा (एमयू) का अर्थ सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटरीकृत और गैर-मीटरीकृत ऊर्जा विक्रय का योग है। इसमें ऊर्जा व्यापार या अनिर्धारित इंटरचेंज या विद्युत की अंतर-राज्यीय विक्रय शामिल किया जाएगा। खुली पहुंच अथवा व्हीलिंग यूनिट को शामिल नहीं किया जाएगा।

5. **सकल व्यापार प्राप्तियां:**

विवरण	**31 मार्च, 20... तक की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**			**31 मार्च, 20... तक की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष)**		
	चालू	**गैर-चालू**	**कुल**	**चालू**	**गैर-चालू**	**कुल**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अपने उपभोक्ताओं को विद्युत की विक्रय के लिए (एलटी, एचटी और ईएचटी)						
वितरण फ्रेंचाइजी को विक्रय हेतु						
अन्य को विद्युत की विक्रय के लिए (जैसे अंतर-राज्यीय विक्रय/ऊर्जा व्यापार/यूआई/						

डीएसएम/अंतर डिस्कॉम विक्रय, आदि)						
विद्युत शुल्क/अन्य कर						
विलंबित भुगतान अधिभार						
अन्य						
(i) कुल						
उपरोक्त (i) में से सरकारी उपभोक्ताओं से संबंधित						
राज्य सरकार के विभाग						
केंद्रीय सरकार के विभाग						

6. ऋण का ब्यौरा:

विवरण		**31 मार्च, 20... तक की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)**					**31 मार्च, 20... तक की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष)**				
		प्रारंभिक शेष	**परिवर्धन**	**भुगतान के लिए देय**	**पुनर्भुगतान**	**अंतिम शेष**	**प्रारंभिक शेष**	**परिवर्धन**	**देय भुगतान**	**पुनर्भुगतान**	**अंतिम शेष**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(7)+(8)-(10)
<u>ऋण (प्रतिभूत और गैर-प्रतिभूत के बीच विभाजित)</u>											
(क)	**दीर्घकालिक ऋण – बैंक/एनबीएफसी/अन्य** (ऋण के प्रयोजन के साथ नाम भी बताएं)										
	(i)										
	(ii)										
	(एन…)										
(ख)	**दीर्घकालिक ऋण – सरकार** (ऋण का प्रयोजन सहित नाम बताएं)										
	(i)										
	(ii)										
	(एन…)										
(ग)	**अल्पावधि ऋण - बैंक/एनबीएफसी/अन्य** (ऋण के प्रयोजन के साथ नाम भी बताएं)										
	(i)										
	(ii)										
	(एन…)										
(घ)	**बॉण्ड** (ऋण के प्रयोजन के साथ बांड										

	का नाम भी बताएं)										
	(i)										
	(ii)										
	(एन…)										
	कुल ऋण : प्रतिभूत										
	कुल ऋण: गैर-प्रतिभूत										
कुल ऋण (प्रतिभूत + गैर-प्रतिभूत)											

टिप्पण: उपर्युक्त सारणी में स्तंभ (2), (6), (7) और (11) में ऋणों का प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वताओं सहित कुल ऋणों को दर्शाता है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण 2: आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) अंतर का विवरण:

क्रम सं.	**मापदंड**	**यूनिट**	**विवरण**	**31 मार्च, 20... तक समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष)**	**31 मार्च, 20... तक समाप्त वर्ष के लिए (पिछले वर्ष)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	सकल इनपुट ऊर्जा	एमयू	एसई का अपना उत्पादन - सहायक खपत + क्रय की गई ऊर्जा (सकल)		
(ii)	कुल व्यय	करोड़ रूपये	लाभ और हानि विवरण के अनुसार कुल व्यय (असाधारण व्यय और उपबंधों सहित)		
(iii)	कुल राजस्व	करोड़ रूपये	लाभ और हानि विवरण के अनुसार कुल राजस्व		
(iv)	आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)	रूपये/किलोवाट घंटा	(ii)*10/क		
(v)	औसत वसूली योग्य राजस्व (एआरआर)	रूपये/किलोवाट घंटा	(iii)*10/क		
(vi)	**एसीएस-एआरआर अंतर**	**रूपये/किलोवाट घंटा**	**(iv)-(v)**		
(vii)	समायोजित कुल राजस्व	करोड़ रूपये	नीचे दिए गए टिप्पण के अनुसार		
(viii)	समायोजित औसत वसूली योग्य राजस्व (एआआर)	रूपये/किलोवाट घंटा	(vii)*10/क		
(ix)	**समायोजित एसीएस - एआरआर अंतर**	**रूपये/किलोवाट घंटा**	**(iv)-(viii)**		

टिप्पण: (i) स्तंभ (2) में सकल इनपुट ऊर्जा से खरीदी गई ऊर्जा और विशेष इकाई के अपने उत्पादन का योग, यदि कोई हो (सहायक खपत का नेट) अभिप्रेत है;

(ii) स्तंभ (2) में समायोजित कुल राजस्व की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

विवरण	31 मार्च, 20... तक समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष)	31 मार्च, 20... तक समाप्त वर्ष के लिए (पिछले वर्ष)
(1)	(2)	(3)
लाभ-हानि विवरण के अनुसार कुल राजस्व		
उपरोक्त कुल राजस्व में शामिल वस्तुओं का समायोजन		
घटाएं: टैरिफ सब्सिडी का बिल भेजा गया और प्राप्त नहीं हुआ		
घटाएं: सकल व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि जोड़ें: सकल व्यापार प्राप्तियों में कमी		
घटाएँ: भविष्य के टैरिफ से वसूली योग्य आय (जैसे नेट संचलन विनियामक आस्थगित शेष)		
घटाएं: राजस्व प्रकृति की अन्य सरकारी सब्सिडी/अनुदान (यदि कुल राजस्व में शामिल है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है)		
घटाएं: पूंजीगत प्रकृति के सरकारी अनुदान (यदि कुल राजस्व में शामिल हो)		
समायोजित कुल राजस्व		

अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण 3: (समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि का विवरण:

क्रम सं.	मापदंड	यूनिट	विवरण	31 मार्च, 20... तक समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष)	31 मार्च, 20... तक समाप्त वर्ष के लिए (पिछले वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क	सकल इनपुट ऊर्जा	एमयू	एसई का अपना उत्पादन - सहायक खपत + क्रय की गई ऊर्जा (सकल)		
ख1	अंतर-राज्यीय विक्रय/ऊर्जा व्यापार/यूआई	एमयू			
ख2	पारेषण हानियां	एमयू			
ग	निवल इनपुट ऊर्जा	एमयू	ग= क-ख1-ख2		
घ	ऊर्जा विक्रय	एमयू	सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विक्रय ऊर्जा, जिसमें कारोबार की गई ऊर्जा की इकाइयाँ/अंतर-राज्यीय विक्रय/यूआई शामिल नहीं हैं		
ङ1	ऊर्जा के विक्रय से राजस्व	करोड़ रूपये	सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा की विक्रय से प्राप्त राजस्व (प्राप्त टैरिफ सब्सिडी सहित) लेकिन कारोबार की गई ऊर्जा/अंतर-राज्यीय विक्रय/यूआई से प्राप्त राजस्व को छोड़कर		
ङ2	प्राप्त टैरिफ सब्सिडी के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से समायोजित राजस्व	करोड़ रूपये	ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व (ऊपर ङ के समान) में से बुक की गई टैरिफ सब्सिडी को घटाकर प्राप्त टैरिफ सब्सिडी को जोड़ दें और वर्ष के दौरान बुक की गई टैरिफ सब्सिडी के निमित्त प्राप्त		

			टैरिफ सब्सिडी को घटा दें।		
च	प्रारंभिक व्यापार प्राप्य	करोड़ रूपये	व्यापार प्राप्य अनुसूची के अनुसार सकल आरंभिक व्यापार प्राप्य।		
छ	अंतिम व्यापार प्राप्य	करोड़ रूपये	(i) व्यापार प्राप्य नोट के अनुसार सकल समापन व्यापार प्राप्य		
			(ii) वर्ष के दौरान सीधे तौर पर (i) से बट्टे खाते में डाली गई कोई राशि		
ज	ऊर्जा के विक्रय के लिए समायोजित समापन व्यापार प्राप्य	करोड़ रूपये	छ(i)+छ(ii)		
झ	संग्रहण दक्षता	%	(ङ+च-ज)*100/ङ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ञ	बिलिंग दक्षता	%	अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण 2 से लिया जाने वाला मूल्य		
ट	प्राप्त इकाइयाँ	एमयू	घ*.झ		
ठ	अप्राप्त इकाइयाँ	एमयू	ग-ट		
ड	**एटीएंडसी हानियां**	**%**	**ठ*100/सी**		

टिप्पण: (i) स्तंभ (2) में संग्रहण दक्षता को 100% तक सीमित किया जाएगा।

(ii) एटीएंडसी हानि की गणना के लिए, राजस्व और व्यापार प्राप्तियों में केवल निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) एलटी, एचटी और ईएचटी उपभोक्ताओं को छूट के बाद विद्युत विक्रय;

(ख) उपभोक्ताओं से प्राप्त अन्य प्राप्तियां (जैसे मीटर किराया, सेवा किराया, बिजली चोरी और कदाचार के लिए वसूली, आदि);

(ग) एफएसी/एफसीए/एफपीपीसीए/पीपीएसी।

(iii) एटीएंडसी हानि की गणना के लिए, राजस्व और व्यापार प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा:

(क) विद्युत प्रभार/अन्य कर;

(ख) ऊर्जा का चक्रण;

(ग) खुली पहुंच विक्रय;

(घ) अंतर-राज्यीय विक्रय/ऊर्जा व्यापार/यूआई/डीएसएम/अंतर डिस्कॉम विक्रय के माध्यम से बिजली की विक्रय;

(ङ) विलंब भुगतान अधिभार/विलंबित भुगतान अधिभार।

[फा.सं.06/03/2021-यूआरएंडएसआई-II(ई-258363)]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2025

G.S.R. 718(E).—In pursuance of sub-section (1) and clause(z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with second proviso to sub-section (1) of section 129 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Electricity Distribution (Accounts and Additional Disclosure) Rules, 2024, dated the 10th October, 2024, and published in Gazette of India vide dated, the 14th October, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**.-(1) These rules may be called the Electricity Distribution (Accounts and Additional Disclosure) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from 01st April, 2026.

2. Applicability.-These rules shall be applicable to Specified Entity.

3. Definition-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) **"Additional Disclosure Statements"** means the statements disclosing particulars as provided in Schedule annexed to these rules;

(c) **"Companies Act"** means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(d) **"Financial Statement"** means Financial Statements referred to in clause (40) of section 2 read with section 129 of the Companies Act;

(e) **"financial year"** means the financial year referred to in clause (41) of section 2 of the Companies Act;

(f) **"Schedule"** means the Schedule annexed to these rules;

(g) **"Specified Entity"** means distribution licensee under the Act excluding Military Engineering Services, Municipal Corporations or Councils, Ports or Trusts, Transport Undertakings, Damodar Valley Corporation, Government Departments not incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), entity solely engaged in distribution of power in Special Economic Zones or any other entity exempted in this regard by the Central Government;

(h) **"tariff subsidy"** means the subsidy provided by the State Government to any specified entity for sale of power at subsidised rates to certain categories of consumers as defined under section 65 of the Act;

(i) **"trade receivable"** means an amount receivable on the account of sale of power or related services rendered in the normal course of business.

(2) The words and expressions used herein and not defined in these rules, shall have the meanings respectively assigned to such words and expressions in the Act or the Companies Act or the rules made there under, as the case may be.

4. **Recognition of regulatory deferral account balances or income recoverable from future tariff.-**(1) For claims or sums to be recoverable through tariff, if any, the Specified Entity shall recognise regulatory deferral account balances or income recoverable from future tariff in its Financial Statement in accordance with applicable Accounting Standards and Guidance note on Accounting for Rate Regulated activities.

(2) The Specified Entity shall review the estimated amount expected to be recovered, refunded or adjusted at least at the end of financial year to reflect the current best estimates.

(3) If expectation differs from previous estimates, the changes should be accounted for as change in accounting estimates in accordance with relevant requirements of applicable Accounting Standard.

(4) The Specified Entity shall follow the norms, mentioned below in Table, at minimum, for impairment of such claim or sum recognised in Financial Statement for which approval for recovery is not available from competent authority:-

TABLE

Age: due from year of recognition	per. cent provisioning
(1)	(2)
More than 3 years and less than or equal to 5 years	25%
More than 5 years and less than or equal to 7 years	50%
More than 7 years	100%;

Provided that where Specified Entity has not filed a petition or appeal in the appropriate Forum for pass through to the consumers within the time limit, as per laws, for the time being in force, for claiming such claims or sums

recognised in such Financial Statement, the Specified Entity, shall provision such balances at 100 per. cent in the year of expiry of such time limit.

Explanations: for the purpose of this notification, it is clarified that:-

(a) above provisioning norms shall be applicable for balances arising after 1st April 2026 onwards;

(b) for balances appearing in the Financial Statement as on 31st March 2026, the Specified Entity shall apply above provisioning norms assuming 31st March 2026 as the year of recognition of such balances; and

(c) Forum means Appropriate Commission or Appellate court.

(5) The Specified Entity shall disclose the basis on which such claims or sums are measured initially and subsequently, including how such amounts are assessed for recoverability and how impairment loss is allocated.

(6) tariff subsidy shall be recognised and accounted for as per the relevant rules made under the Act.

5. **Provisioning of trade receivables.-**The minimum provisioning requirement for a Specified Entity on its trade receivables from all category of consumers in the Financial Statements shall be as Table below:

Table

Serial number	**Trade receivables outstanding for following periods from due date of payment**	**per. cent provisioning**		
		financial year 2026-27	**financial year 2027-28**	**financial year 2028-29 and onwards**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0 and up to 90 days	-	-	-
2.	Exceeding 90 days and up to 180 days	5%	10%	15%
3.	Exceeding 180 days and up to 1 year	20%	25%	30%
4.	Exceeding 1 year and up to 2 years	35%	40%	45%
5.	Exceeding 2 years and up to 3 years	55%	60%	75%
6.	More than 3 years	75%	80%	100%
7.	dues from permanently disconnected consumers	75%	75%	75%:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to:-

(i) trade receivables from Government Consumers; or

(ii) Specified Entity having trade receivable days less than or equal to ninety days on aggregate basis:

Provided further that the appropriate Commission may set a higher provisioning requirement on the recommendations of a Committee set up by the State Government which shall consist of Principal Secretary (Power), the Principal Secretary (Finance) and the Chairman or Managing Director or both of the Specified Entity as members.

Explanation.-For the purposes of this rule, the expressions,-

(i) Government consumers means the departments, urban local bodies, rural local bodies, public sector undertakings and the like owned or belonging to the State Government and the Central Government; and

(ii) Trade receivable days means trade receivables at the end of the financial year divided by average revenue per day.

6. **Content and form of Additional Disclosure Statements**-(1) In addition to the statutory disclosures as mandated under the Companies Act, the Specified Entity shall also prepare the Additional Disclosure Statements for each financial year in the form and manner as provided in the Schedule.

Explanation.-For the purposes of this rule, it is hereby clarified that the Additional Disclosure Statements are required to be prepared for the power related business of the Specified Entity.

(2)The Additional Disclosure Statements shall be part of the Financial Statements prepared by the Specified Entity and are to be annexed to the Financial Statements as the last disclosure titled 'Additional Disclosure Statements' under the notes to accounts of the Financial Statements:

Provided that in the first year of preparation of Additional Disclosure Statements, the Specified Entity shall have the option to include Additional Disclosure Statements either in the annual report or in the Financial Statements.

(3)The Additional Disclosure Statements shall comprise the following statements as annexed to this rule, namely:-
(i) supplementary disclosures to Financial Statements;
(ii) statement of Average Cost of Supply-Average Revenue Realised gap; and
(iii) statement of Aggregate Technical and Commercial loss.

Explanation.-For the removal of doubts, it is hereby clarified that for the financial year 2026-27 preparation of Additional Disclosure Statements, comparative figures of previous financial year shall be optional.

7. **Statement of compliance.-**A statement of compliance shall be given by the management of Specified Entity at the beginning of the Additional Disclosure Statements confirming that the Additional Disclosure Statements are prepared and presented in the form and manner provided in the Schedule.

Schedule: Additional Disclosure Statements (ADS)

ADS 1: Supplementary disclosures to Financial Statements

1. **Revenue from operations:**

Particulars	**For the year ended 31st March, 20.. (current year)**	**For the year ended 31st March, 20.. (previous year)**
(1)	(2)	(3)
(a) Revenue from sale of energy		
Sale of power to own consumers (Low Tension (LT), High Tension (HT) and Extra High Tension (EHT))		
Fuel Adjustment Charge (FAC)/ Fuel Cost Adjustment (FCA)/ Fuel and Power Purchase Cost Adjustment (FPPCA)/ Power Purchase Adjustment Charge (PPAC)		
Sale to Distribution Franchisee		
Sale of power to others (such as inter-State sale/ energy traded/Unscheduled Inter-change (UI)/Deviation Settlement Mechanism (DSM)/inter DISCOM sale, etc.)		
Other receipts from consumers (such as meter rents, service rentals, recoveries for theft of power and malpractices, etc.)		
(i) Total		
Less: rebate to consumers (if any, other than cash discount) **(ii)**		
Revenue from sale of energy without tariff subsidy (i-ii)		
Electricity duty/ other taxes billed to consumers Electricity duty/ other taxes payable to Government		
Sub-total of revenue from sale of energy		

(b) Other operating income		
Wheeling charges		
Open access charges		
Others		
(c) Subsidy payable by State Government in accordance with the relevant rules as per the number of units supplied to subsidized categories according to energy accounts multiplied by the per unit subsidy		
Subsidy received		
Subsidy yet to be received		
Total revenue from operations (a + b + c)		

2. Details of revenue from sale of energy:

Particulars	**For the year ended 31st March, 20.. (For Current and Previous Year)**					
	Energy sold - metered (MU)	**Energy sold - un-metered (MU)**	**Gross energy sold (MU)**	**Revenue from sale of energy without tariff subsidy**	**Tariff subsidy billed**	**Tariff subsidy received (out of (6))**
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)
Domestic						
Commercial						
Agricultural						
Industrial						
Others:						
Public street lighting						
Public water works						
Railways						
Bulk supply						
Distribution franchisee						
Inter-State sale/ energy traded/UI/DSM						
Others (may specify nature)						
(i) Total						
Out of (i) above, related to Government consumers						
State Government consumers						
Central Government consumers						

3. Details of number of consumers:

Particulars	**For the year ended 31st March, 20.. (For Current and Previous Year)**											
	As on 1st April 20..				**During the year**				**As on 31st March 20..**			
	Number of consumers - pre-paid meters	**Number of consumers - other meters**	**Number of consumers - un-metered**	**Total no. of consumers**	**Number of consumers added - pre-paid meters**	**Number of consumers added - other meters**	**Number of consumers - un-metered**	**Number of consumers permanently disconnected**	**Number of consumers - pre-paid meters**	**Number of consumers - other meters**	**Number of consumers - un-metered**	**Total no. of consumers**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Domestic												
Commercial												
Agricultural												
Industrial												
Others:												
Public street lighting												

Public water works												
Railways												
Bulk supply												
Miscellaneous												
Total												

4. Details of cross subsidy:

For the year ended 31st March, 20.. (For Current and Previous Year)							
Particulars	**Average Cost of Supply (ACoS) (Rs./kWh)**	**Notified tariff**	**Notified subsidy**	**Gross energy sold (MU)**	**Revenue from sale of energy without tariff subsidy (Rs. Crore)**	**Average Billing Rate (ABR) (Rs./kWh)**	**Cross subsidy (Rs./kWh) (ACoS - ABR)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(2)-(7)
Domestic							
Commercial							
Agricultural							
Industrial							
Others:							
Public street lighting							
Public water works							
Railways							
Bulk supply							
Miscellaneous							
Total							

Note: (i)In column (2) Average Cost of Supply (ACoS) means total expenses as per statement of profit and loss divided by gross energy sold;
(ii) In column (3) Notified tariff means the tariff applicable to the consumer category as per the relevant tariff order;
(iii)In column (5) Gross energy sold (MU)means aggregate of metered and unmetered energy sale to all category of consumers. Energy traded or unscheduled interchange or inter-State sale of power to be included. Open access or wheeling units shall not be included.

5. Gross trade receivables:

Particulars	**As at 31st March, 20.. (current year)**			**As at 31st March, 20.. (previous year)**		
	Current	**Non-current**	**Total**	**Current**	**Non-current**	**Total**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
For sale of power to own consumers (LT, HT and EHT)						
For sale to distribution franchisee						
For sale of power to others (such as inter-State sale/energy traded/UI/DSM/inter DISCOM sale, etc.)						
Electricity duty/ other taxes						
Late payment surcharge						
Others						
(i) Total						
Out of (i) above, related to Government consumers						

State Government departments						
Central Government departments						

6. Details of borrowings:

Particulars		**As at 31st March, 20.. (current year)**					**As at 31st March, 20.. (previous year)**				
		Opening balance	**Additions**	**Due for payment**	**Repayments**	**Closing balance**	**Opening balance**	**Additions**	**Due for payment**	**Repayments**	**Closing balance**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(7)+(8)-(10)
Borrowings(bifurcate between secured and un-secured)											
(a)	**Long term loans – banks/NBFC/ others** (specify name along with purpose of loan)										
	(i)										
	(ii)										
	(n…)										
(b)	**Long term loans – Government**(specify name along with purpose of loan)										
	(i)										
	(ii)										
	(n…)										
(c)	**Short term loans - banks/NBFC/others**(Specify name along with purpose of loan)										
	(i)										
	(ii)										
	(n…)										
(d)	**Bonds** (specify name of bonds along with purpose of loan)										
	(i)										
	(ii)										
	(n…)										
	Total borrowing: secured										
	Total borrowing: un-secured										
Total borrowing (secured + un-secured)											

Note: In column (2), (6), (7) and (11) opening balance and closing balance of borrowings in above table reflects total borrowings including current maturities of long-term borrowings.

ADS 2: Statement of Average Cost of Supply (ACS) –Average Revenue Realised (ARR) gap:

Serial number	**Parameter**	**Units**	**Description**	**For the year ended 31st March, 20.. (current year)**	**For the year ended 31st March, 20.. (previous year)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	Gross input energy	MU	SE's own generation - auxiliary consumption + energy purchased (Gross)		
(ii)	Total expenses	Rs. crore	Total expenses as per statement of profit and loss(including extraordinary expenses & provisions)		
(iii)	Total revenue	Rs. crore	Total revenue as per statement of profit and loss		
(iv)	Average Cost of Supply (ACS)	Rs/kwh	(ii)*10/A		
(v)	Average Realizable Revenue (ARR)	Rs/kwh	(iii)*10/A		
(vi)	**ACS - ARR gap**	**Rs/kwh**	**(iv)-(v)**		
(vii)	Adjusted total revenue	Rs. crore	As per note below		
(viii)	Adjusted Average Realizable Revenue (ARR)	Rs/kwh	(vii)*10/A		
(ix)	**Adjusted ACS - ARR Gap**	**Rs/kwh**	**(iv)-(viii)**		

Note: (i) In column (2) gross input energy means sum of energy purchased and special entity's own generation, if any (net of auxiliary consumption);
(ii) In column (2) adjusted total revenue to be calculated as below:

Particulars	**For the year ended 31st March, 20.. (current year)**	**For the year ended 31st March, 20.. (previous year)**
(1)	(2)	(3)
Total revenue as per statement of profit and loss		
Adjustments of items included in total revenue above		
Less: tariff subsidy billed and not received		
Less: increase in gross trade receivables Add: decrease in gross trade receivables		
Less: Income recoverable from future tariffs (like net movement Regulatory Deferral Balances)		
Less: other Government subsidy/ grant of revenue nature (if included in total revenue but not received)		
Less: Government grants of capital nature (if included in total revenue)		
Adjusted total revenue		

ADS 3: Statement of Aggregate Technical and Commercial (AT&C) loss:

S.No.	Parameter	Unit	Description	For the year ended 31st March, 20.. (currentyear)	For the year ended 31st March, 20.. (previous year)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Gross input energy	MU	SE's own generation - auxiliary consumption + energy purchased (gross)		
B1	Inter-State sale/ energy traded/UI	MU			
B2	Transmission losses	MU			
C	Net input energy	MU	C= A-B1-B2		
D	Energy sold	MU	Energy sold to all categories of consumers excluding units of energy traded/ inter-State sales/UI		
E1	Revenue from sale of energy	Rs crore	Revenue from sale of energy to all categories of consumers (including tariff subsidy booked) but excluding revenue from energy traded/ inter-State sales/ UI		
E2	Adjusted Revenue from sale of energy on tariff subsidy received basis	Rs. crore	Revenue from sale of energy (same as E above) minus Tariff Subsidy Booked plus Tariff Subsidy received against Tariff subsidy booked during the year		
F	Opening trade receivable	Rs. crore	Gross opening trade receivable as per trade receivable schedule.		
G	Closing trade receivables	Rs. crore	(i)Gross closing trade receivables as per trade receivable note		
			(ii) Any amount written off during the year directly from (i)		
H	Adjusted closing trade receivable for sale of energy	Rs. crore	G(i)+G(ii)		
I	Collection efficiency	%	(E2+F-H)*100/E1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Billing efficiency	%	Value to be taken from Additional Disclosure Statement 2		
K	Units realized	MU	D*I		
L	Units un-realized	MU	C-K		
M	**AT&C losses**	**%**	**L*100/C**		

Note:(i) In column (2) collection efficiency to be capped at 100%.

(ii) For calculation of AT&C loss, revenue and trade receivables shall include only:

(a)Sale of power to LT, HT and EHT consumers net of rebate to consumers;

(b)Other receipts from consumers (such as meter rents, service rentals, recoveries for theft of power and malpractices, etc.);

(c)FAC/FCA/ FPPCA/PPAC.

(iii) For calculation of AT&C loss, revenue and trade receivables shall exclude:

(a) Electricity duty/other taxes;

(b) Wheeling of energy;

(c) Open access sale;

(d) Sale of power through inter-State sale/ energy traded/UI/DSM/ inter DISCOM sale;

(e) Delayed payment surcharge/ late payment surcharge.

[F. No.06/03/2021-UR&SI-II(E-258363)]
SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.29 15:32:04 +05'30'